RJPP, Vol. XXIII, No.I, Oct.24-Mar.25, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411
Impact Factor 8.858

भारतीय राजनीति और युवा भागीदारी

डॉ0 पंकज शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर
इतिहास विभाग
एन. ए. एस. कॉलेज, मेरठ
ईमेलः dr.pankajsharma1656@gmail.com

डॉ0 रोताश
एसोसिएट प्रोफेसर
इतिहास विभाग
गाँधी आदर्श कॉलेज,
समालखा

सारांश

उत्तर प्रदेश में किए गए नृवंशविज्ञान संबंधी फील्डवर्क के माध्यम से, हम प्रदर्शित करते हैं कि कैसे जाति और युवाओं की साझा भावना चुनावी चक्रों के दौरान राजनीति को प्रभावित करती है। उत्तर भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवा नए सामाजिक समूह बना रहे हैं और जाति संघों के सदस्य बन रहे हैं जो चुनावी मौसम के दौरान महत्वपूर्ण हैं। वे विभिन्न वर्गों, धर्मों और जातियों में भी शामिल हो रहे हैं। भारत के शिक्षित युवाओं की राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रकाश में, यह लेख जातियों और राजनीति के बीच संबंधों की पड़ताल करता है।

मुख्य शब्द

राजनीतिक भागीदारी, युवा, जाति, वर्ग रोजगार आदि।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 28.01.2025
Approved: 19.03.2025

डॉ0 पंकज
डॉ0 रोताश

भारतीय राजनीति और युवा भागीदारी

RJPP Oct.24-Mar.25,
Vol. XXIII, No. I,
Article No. 10
Pg. 81-88

Online available at:
https://anubooks.com/journal-volume/rjpp-sept-2025-vol-xxiii-no1

परिचय

यह लेख 2019–2020 में मेरठ में जातियों और उनका राजनैतिक तंत्र में बदलते परिदृश्य के बारे में युवाओं के विचारों की जांच करता है। हमारा तर्क है कि भारत में जाति की मुख्यधारा की समझ के विपरीत, मेरठ की शिक्षा और रोजगार में मौजूदा संकट, साथ ही युवाओं के बीच जुड़ी भावना, सबसे अमीर वरिष्ठ जाति के लोगों और सबसे गरीब दलितों के बीच दोस्ती, सौहार्द और तीव्र बुराई के नए अवसर प्रस्तुत करती है। इसके अलावा, कभी–कभी जाति और वर्ग के मतभेदों की परवाह किए बिना युवा लोग राज्य के खिलाफ सामूहिक विरोध शुरू करने के लिए इकट्ठा होते हैं। 2019–20 में किए गए अध्ययनों के डेटा का उपयोग करते हुए, हम प्रदर्शित करते हैं कि कैसे सौहार्द और एकता की भावना धीरे–धीरे कम होती गई क्योंकि कुछ युवा पुरुषों ने अपने स्थानीय राजनीतिक प्रभाव का लाभ उठाया। उच्च जाति के ''फिक्सर'' और दलित राजनेताओं की एक नई पीढ़ी द्वारा अंतर–जाति युवा एकजुटता को अंदर से कमजोर किया जा रहा है जो स्वार्थी एजेंडे का पीछा कर रहे हैं।

राज्य विधानसभा में, मध्यम वर्ग, मुस्लिम और दलित युवाओं का बहुमत यह निर्धारित करता है कि सरकार किसकी बनेगी। छात्र राजनीति में ''फिक्सर'', जैसे कि दलित और जाट, जिनके कार्य समूहों द्वारा प्रदर्शनों को कमजोर करते हैं। बल्कि, इस शोधपत्र का ध्यान जाति और राजनीति पर है, जिसमें युवाओं पर विशेष जोर दिया गया है। विशेष रूप से, हम उन स्थितियों को देखते हैं, जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातियाँ, विशेष रूप से मेरठ और बागपत जिलों में, किसी विशेष राजनीतिक दल का पक्ष लेती हैं या उसका विरोध करती हैं।

थॉमस हैनसेन (1996) के अनुसार, 1990 के दशक के दौरान बॉम्बे में, निम्न मध्यम वर्ग के युवा पुरुषों ने हिंदू राष्ट्रवाद के राजनीतिक आकाओं के रूप में पहचान बनाई और स्थिर नौकरियों से व्यापक रूप से वंचित होने के परिणामस्वरूप मुस्लिम विरोधी विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। 2009 में प्रेम चौधरी द्वारा हरियाणा में बेरोजगार जाट (मध्यम जाति) युवाओं पर शोध किया गया था, जो पंचायत परिशदों में हिंसक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह, मार्टिन रोजर्स (2008) का तर्क है कि दक्षिण भारतीय कॉलेज परिसर में शिक्षित लेकिन बेरोजगार दलितों में जाति बनाने की प्रवृत्ति होती है।

अनिरुद्ध कृष्ण (2002) ने ग्रामीण पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के बारे में लिखा था, जिन्होंने राज्य वार्ता में गरीबों का समर्थन करने के लिए विभिन्न जातियों के व्यक्तियों के साथ सहयोग किया। युवाओं पर वर्तमान शोध का यह अवलोकन उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति के बारे में सोचने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। क्या युवा वर्ग और जाति की सीमाओं से परे संगठित हो रहे थे?

जाति और राजनीति के बीच संबंध

उत्तर प्रदेश में युवा पुरुषों ने 2000 के दशक की शुरुआत में वयस्क होने के बाद जो सामाजिक–आर्थिक रुझान देखे, उनसे असंतुष्ट युवाओं की एक पीढ़ी पैदा हुई है। युवा लोग कई तरह से इन अनिश्चितताओं से निपटने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी का अनुमान लगाने के लिए तीन सामाजिक वर्गों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लगभग 20% लोग उच्च जातियों के हिंदू हैं, मुख्य रूप से ब्राह्मण और ठाकुर। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में, ये जातियाँ भूमि स्वामित्व, मजदूरी और नगरपालिका सरकार की नौकरशाही पर हावी थीं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में, मध्यम वर्ग से संबंधित हिंदू

परिवारों का दूसरा समूह अक्सर राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर प्रभाव रखता है। उत्तर–पश्चिम में जाट परिवार हैं, और दक्षिण–पश्चिम और पूर्व में यादव परिवार हैं। मुस्लिम, दलित और तथाकथित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कम भाग्यशाली सदस्य, जिन्हें जाति पदानुक्रम में दलितों से कानूनी रूप से उच्च माने जाने के बावजूद सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित जातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उत्तर प्रदेश में शेष आबादी का बहुमत बनाते हैं। मुसलमानों और दलितों के बीच, यूपी में एक अभिजात वर्ग है। हालाँकि, मुस्लिम, दलित और निम्न–वर्ग के ओबीसी के पास आमतौर पर बहुत कम भौतिक संपत्ति होती है और वे अनिश्चित परिस्थितियों में काम करते हैं।

अधिकांश युवा लोग जानते हैं कि वे अब आखिरकार काम कर सकते हैं। निजी व्यवसाय के मालिकों ने युवाओं को जो उम्मीद दी है, वह बहुत सराहनीय है। उन्होंने युवाओं को यह समझाकर निजी विश्वविद्यालयों, साथ ही अन्य शिक्षण संस्थानों और स्कूलों में नामांकन बढ़ाने का प्रयास किया कि वे ''आखिरकार'' प्रतिष्ठित नौकरियां पैदा करने में सक्षम होंगे यदि वे उचित डिप्लोमा पैकेज प्राप्त कर सकते हैं।

हजारों दलितों ने 2004 और 2005 में उम्मीद की थी कि अगर दलित समर्थक बीएसपी अपने दम पर यूपी पर कब्जा कर लेती है तो वे स्थानीय राजनीतिक समूहों में शामिल होने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। हालांकि, प्रतीक्षा का राजनीतिक आयाम दलित, जाट और मुस्लिम भावनाओं की तरह प्रमुख नहीं था, जो अत्यधिक समय और देरी को नियंत्रित करने की आवश्यकता के बारे में थी। मेरठ में युवा लोग आम तौर पर उन जगहों पर एकत्र होते थे जो शहर के बाहर सूचना और परिवहन की आवाजाही से जुड़े होते थे। वे अक्सर सुबह आठ बजे और एक बार फिर रात में मेरठ स्टेडियम के पास प्रमुख सड़कों के चौराहे पर एकत्र होते थे। ये स्थान बेरोजगार युवाओं के लिए एक सभा स्थल के रूप में काम करते थे, जो अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाना चाहते थे और साथ ही एक तरह का ''ठिकाना'' भी था, जहाँ से वे मेरठ में लोगों, सामानों और छवियों के आने–जाने को देख सकते थे। (जेफरी, 2010)।

सड़क के कोने और चाय की दुकानें लोगों के लिए सभा स्थल के रूप में काम करती थीं। सीसीएसयू में, जाति और धर्म के आधार पर पुरुषों के छात्रावासों के बीच कुछ अंतर थे। निचली जाति के छात्रों ने दावा किया कि मेरठ क्षेत्र में दलितों के लिए विशेष रूप से निर्मित छात्रावास की उपस्थिति उन्हें उच्च जाति के डर से बचाने में महत्वपूर्ण थी। फिर भी, जाट, दलित, मुस्लिम और अन्य जातियाँ अक्सर चाय की दुकानों के पीछे खुलकर, मिलनसार और अक्सर गर्मजोशी से बातचीत करती थीं। जाति और धार्मिक सीमाओं से परे जाने की इच्छा ने मेरठ के चायघरों में उभरी एकजुटता के रूपों को अलग किया। जाति की यह मान्यता कि भोजन साझा करना या लार के संपर्क से दूसरों को संक्रमित किया जा सकता है, तब दूर हो गई जब मुसलमानों, दलितों और हाई स्कूल के छात्रों ने चाय और नमकीन स्नैक्स साझा किए और मौखिक रूप से सिगरेट साझा की।

राजनीति के क्षेत्र

इस अध्ययन में, हमने जाति व्यवस्था के पक्ष में राजनीति में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की जांच की। शुरू में, हमारा ध्यान इस बात पर था कि मेरठ में युवाओं के लिए राजनीतिक चर्चाएँ समय की बर्बादी हैं और यह उनके शैक्षणिक विकास के लिए कितना हानिकारक है। इन नुक्कड़ चर्चाओं के माध्यम से, हम पिछले चुनाव के दौरान युवाओं के दृष्टिकोण की धारणा में एक महत्वपूर्ण

बदलाव देख पाए। युवा राजनीतिक रूप से राष्ट्रवाद और युवाओं के लिए जाति व्यवस्था के आदेशों की वकालत करने पर केंद्रित थे। नतीजतन, भारतीय जनता पार्टी इस बदलाव का लाभ उठाती है, जबकि स्थानीय पार्टी मतदाताओं से समर्थन कम करते हुए अपने एजेंडे और पहचान को परिभाषित करने के लिए संघर्ष करती है। विशेष रूप से मेरठ में, चाय का कोना युवाओं के बीच राजनीतिक चर्चा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे उन्हें राजनीतिक कार्रवाई के बारे में अधिक जानने और अपने दोस्तों और परिवार की मतदान आदतों को प्रभावित करने में मदद मिलती है।

युवाओं का आंदोलन काफी हद तक बेरोजगारी पर निर्भर करता है, एक ऐसा विषय जिस पर वर्तमान प्रशासन भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। छात्रों का अपने डिग्री प्रमाणपत्रों के लिए इंतजार करना, जो भ्रष्टाचार के संदर्भ में उनकी पीड़ा के सबसे शक्तिशाली संकेतक के रूप में कार्य करता है, यही कारण है कि यह युवा लोगों के दिमाग में एक गर्म विषय है।

विभिन्न चौनलों के माध्यम से मदद के लिए एक छात्र की दलील सुनने के बाद, छात्र छात्रावास के निवासियों के साथ–साथ पास के विश्वविद्यालय और आस–पास के क्षेत्रों में कॉल करते थे, और वे दोस्तों से जुड़ने के लिए सेल फोन का उपयोग करते थे। अपने विश्वसनीय सलाहकारों के साथ संभावित कार्रवाई के तरीकों पर बात करने के बाद, वह अक्सर विरोध प्रदर्शनों की योजना बनाते थे, जिसमें मुस्लिम और दलितों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र शामिल होते थे।

संक्षेप में, मेरठ के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित राजनीतिक रूप से प्रेरित युवाओं ने देश के छात्र विरोधों को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाईः मध्य–जाति के सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन 2020 तक, मेरठ शहर का राजनीतिक माहौल काफी हद तक शांत हो गया था। एक कारण छात्र संघ चुनावों से संबंधित नियमों में संशोधन था। भाजपा की नेतृत्व शैली ने उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी। अब समय आ गया है कि राजनीतिक नेता बोलें और विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए चुनाव करवाएँ।

मध्यम वर्ग के छात्र नेताओं की संख्या में वृद्धि, जिन्होंने आंतरिक विरोधों को विफल कर दिया, सामूहिक छात्र कार्रवाई के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारक था। परिसर और आसपास के समुदायों में छात्र निकाय की ताकत के कारण, जाटों ने ऐतिहासिक रूप से विश्वविद्यालय संघों में शीर्ष पदों पर कब्जा किया है। कई छात्र नेता विश्वविद्यालय और प्रशासनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं; इन विरोधों को अक्सर स्थानीय समाचार पत्रों और टेलीविजन स्टेशनों में दोस्तों द्वारा अनुकूल रूप से कवर किया जाता है, जो विभिन्न राजनीतिक दलों में स्थानीय राजनीति के लिए अवसर खोलता है। कभी–कभी, कुछ छात्र नेताओं द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों से लाभ भी उठाते हैं।

पिछले दस सालों से छात्रसंघ में सीट जीतने के बाद, ज़्यादातर छात्र नेताओं ने राजस्व पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके उदाहरणों में सीसीएसयू से जुड़े कॉलेजों में पिछले दरवाजे से प्रवेश की व्यवस्था करना और विश्वविद्यालय प्रशासन और लाभ कमाने वाले शैक्षणिक उद्यमियों के बीच बिचौलियों के रूप में काम करना शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मौजूदा खेल खत्म हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और सभी के लिए पारदर्शी बना दिया है, जो एक महत्वपूर्ण कारक है। भ्रष्टाचार के स्तर में कमी के लिए आरटीआई भी जिम्मेदार है।

हाल के वर्षों में राजनीति से जुड़े अधिकांश छात्र नेता हाल ही में हुए विधान सभा चुनाव में भाजपा के कारण अपने रोजगार की कमी से परेशान थे, जिसमें भाजपा ने उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से सत्ता हासिल की थी। उन्होंने दावा किया कि 2017 का चुनाव जीतने के बाद भाजपा ''कट्टरपंथी'' हो गई थी और इसके नेता अपने मुख्य निर्वाचन क्षेत्र के साथ संबंध बनाए रखने की तुलना में दिल्ली में सत्ता हासिल करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एक छात्र नेता ने कहा, ''अयोध्या मंदिर आंदोलन ने 1990 के दशक में भाजपा को एक आंदोलन के रूप में जन्म दिया।'' वरिष्ठ आंदोलन के नेताओं ने पूरे उत्तर प्रदेश में घूम–घूम कर सूचना का प्रसार किया। नाराजगी का एक विशेष स्रोत योगी आदित्य नाथ द्वारा स्थानीय ब्राह्मणों, जाटों और गुर्जरों को भाजपा के जिला अध्यक्ष पद और विधान सभा (एमएलए) सीटें देने का विकल्प था। अधिकांश छात्रों ने इस प्रथा को इस बात का सबूत माना कि सबसे धनी, उच्च जातियों ने पार्टी पर नियंत्रण कर लिया था, जबकि छात्र नेताओं ने इसका बचाव किया और दावा किया कि जातिवाद के आरोपों को रोकने के लिए यह आवश्यक था। ऐतिहासिक पहचान के स्वामित्व को लेकर ठाकुर और गुर्जर के बीच संघर्ष हाल के वर्षों में भाजपा के लिए राजनीतिक सिरदर्द बन गया है।

व्यावहारिक अनुभव के अनुसार, राजनीति के बारे में सोचने के तरीके पर उम्र का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पिछले दो चुनावों में युवाओं ने राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे हम विश्लेषण कर सकते हैं कि युवाओं की पारंपरिक राजनीतिक सोच किस तरह तेजी से विकसित हो रही है। युवाओं का राजनीति के बारे में एक अलग नजरिया है और उनमें राष्ट्रवाद की भावना प्रबल है। हम पिछले दो चुनावों में जाति व्यवस्था के प्रभुत्व की जल्दी से जांच कर सकते हैं ताकि स्थानीय पार्टी को युवाओं की नजर में राजनीतिक कलंक से उबरने में मदद मिल सके और इस बदलाव से भाजपा को फायदा हो। राजनीतिक विमर्श का अध्ययन करने के बाद, हमने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में, परिवार का आकार भी तय करता है और हमारे आधुनिक समाज में, संयुक्त परिवार अधिक आम होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में लोग अधिक तर्कसंगत हैं और अपने हित में कार्य करते हैं। पहले, अधिकांश संयुक्त परिवारों में, परिवार का केवल एक ही मुख्य सदस्य होता था जो सभी बड़े फैसले लेता था, परिवार के अन्य सदस्य उसके नेतृत्व का पालन करते थे। राजनीतिक मुद्दों को संभालने के लिए एक व्यवस्था थी। राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों की एक छोटी संख्या राजनीतिक नेता को गाँव के मुद्दों के बारे में सूचित करती थी और चुनाव होने पर मतदान करती थी। भारतीय गांवों में सामाजिक समस्याएं सामाजिक संरचना के साथ–साथ बदलती रहती हैं।

स्वतंत्रता के बाद, चुनौती सड़कें बनाने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश करने की थी। समुदाय के नेता भी अपने समुदायों में काम करना पसंद करते थे, जैसा कि संसद में बड़ौत सीट पर आरएलडी के बहुमत के कब्जे से स्पष्ट है, जिसे अपने नेताओं की जाति से संबद्धता और इस तथ्य के कारण ''जाटों के वर्चस्व वाली पार्टी'' कहा जाता था कि इस क्षेत्र में पूरा किए गए अधिकांश कार्य–सड़कें, स्कूल, कॉलेज, बिजली घर, आदि–जाट भूमि पर किए गए थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में केवल शिक्षित युवा ही तर्क के आधार पर विवाद करते हैं कुछ उत्तरदाता इस आधार पर जवाब नहीं देते हैं और सेवा कर्मी भी राजनीति के बारे में जानकार होते हैं और तथ्य के आधार पर विवाद करते हैं। वर्तमान में, उत्तरदाताओं की आय का स्तर बढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों

में जाति का प्रभाव कम है। निचली जातियों के उत्तरदाताओं के पास अब संपत्ति है और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी स्थिति बढ़ रही है। हम व्यवहार में देखते हैं कि जमीनी राजनीति और पंचायती राज में गुटीय समूहों की भागीदारी के कारण जाति कानून धीरे–धीरे बदल रहे हैं, जहां ये गुट स्थानीय राजनीति और प्रशासन में स्थान हासिल करने के लिए तेजी से काम करते हैं। ग्रामीण राजनीति पर हमारे शोध से पता चलता है कि जाति स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जाति व्यवस्था लोगों के वोट को प्रभावित करती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। यह देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में एकल परिवार संयुक्त से एकल परिवार में बदल रहा है त्यागी जाति द्वारा अपने राजनीतिक प्रतिनिधि श्रीकांत त्यागी को जेल से छुड़ाने के लिए हाल ही में किए गए प्रयासों ने भाजपा पर दबाव डाला है, और इसके परिणाम 2022 के अंत में होने वाले खतौली विधानसभा चुनाव में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा, जब हम राज्य की राजनीति के ऐतिहासिक विवरणों की जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि जाति व्यवस्था का राज्य की राजनीति पर 1900 के दशक में प्रभाव था, जब बसपा ने जाति की राजनीति पर शासन किया और अनुसूचित जाति को सशक्त बनाया। पिछले दस वर्षों में, यह महत्वपूर्ण रहा है कि जाति समीकरण को फिर से स्थापित किया जाए। कुछ उत्तरदाताओं ने बताया है कि इस बार जाति कारक की जगह जाति कारक ने ले ली है, और भाजपा राष्ट्रवाद के पक्ष में मतदाताओं की मानसिकता को प्रभावित करने और उत्तर प्रदेश में जाति कारक को बदलने में सफल रही है। इन दिनों उत्तरदाताओं का रवैया तेजी से बदल रहा है। उन्हें लगता है कि जाति की भागीदारी जाति के वास्तविक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और जाति के प्रतिनिधि राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मतदाता केवल चुनाव के मौसम में ही मतदान करते हैं और जाति के निरंतर विकास और राजनीति में प्रतिनिधित्व का समर्थन करने के लिए राजनीतिक दलों पर राजनीतिक दबाव डाला जाना चाहिए।

निष्कर्ष

अधिकांश उत्तरदाताओं, जो स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, का मानना है कि मानवीय राजनीतिक भागीदारी ही सच्चे विकास की कुंजी है। राजनीति समाज को नियंत्रित करती है और प्रत्येक व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति के साथ–साथ किसी समूह या जाति की स्थिति को भी निर्धारित करती है। वर्तमान युग स्थानीय राजनीति में सामाजिक आंदोलनों द्वारा चिह्नित है। 2021 में, भारतीय किसान युनियन ने दिल्ली के यूपी गेट पर एक किसान आंदोलन का आयोजन किया, जिसमें भाग लेने वाले किसानों के लिए अस्थायी आवास उपलब्ध कराया गया। ये आंदोलन जातिगत राजनीति और किसान राजनीति दोनों से काफी प्रभावित हैं।

इस आंदोलन ने उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति को मजबूत किया और स्थानीय राजनीति के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे के नेतृत्व में इस आंदोलन में जाट जाति प्रमुखता से उभरी और केंद्र सरकार पर किसान बिल से संबंधित तीन कानूनों को रद्द करने का दबाव बनाया। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी समाचार पत्र लोगों के लिए राजनीतिक जानकारी का एक प्रमुख स्रोत हैं। वैश्वीकरण और उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में, ग्रामीण राजनीतिक गतिविधि ा के बारे में जानकारी का उतना मूल्यवान स्रोत नहीं है जितना पहले हुआ करता था।

भारतीय राजनीति में, मतदाता व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जाति है। भारत का राजनीतिक इतिहास बताता है कि जाति आज भी देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ उत्तरदाताओं को जातियों की आबादी और राजनीति में उनके सटीक प्रतिनिधित्व की पूरी समझ थी। कुछ अन्य हाशिए की जातियों और दलितों ने भी स्वतंत्रता के बाद राजनीति में निचली जातियों के प्रतिनिधित्व के कम संपीड़न को दोशी ठहराया, जब उच्च जातियों ने राजनीतिक व्यवस्था पर नियंत्रण कर लिया और अपना प्रभुत्व ओबीसी और दलितों तक भी बढ़ा दिया।

अधिकांश उत्तरदाताओं को लगता है कि जाति सम्मेलन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच जागरूकता नहीं बढ़ाते हैं; केवल 19.66% उत्तरदाता इस बात से सहमत हैं कि लोगों की जागरूकता बढ़ाने में जाति संघ महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों, आम लोगों को राजनीतिक धारणाओं के बारे में शिक्षित करने और जाति हितों के बारे में आम लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ सम्मेलन आयोजित करना आम बात है। उत्तरदाताओं का जाति व्यवस्था में विश्वास है, और अधिक लोग जाति जागरूकता बढ़ाने और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने में शामिल हो रहे हैं। जाति संघ राजनीतिक विकास के वर्तमान युग में, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आम जनता और स्थानीय आबादी राजनीति को समग्र रूप से मानव विकास की कुंजी के रूप में समझे और लाभकारी नीतियों को बनाने और उनसे लाभ उठाने के लिए मानव विकास के लिए राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। चुनाव के दौरान मतदाताओं के साथ बातचीत के माध्यम से, हम सीखते हैं कि जाति के नेताओं का लोगों की मतदान आदतों पर प्रभाव पड़ता है। यह देखना आम बात है कि किसी जाति के जाने–माने राजनीतिक हस्तियों को राज्य की राजनीति को प्रभावित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लिए समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए अक्सर फिल्म सितारों को भी आमंत्रित किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद, राज्य और संघीय स्तर पर जाति भागीदारी में असमानताएँ भी देखी गईं। जनसंख्या अनुपात की तुलना में, उच्च जाति के कुछ सदस्य दूसरों की तुलना में राजनीति में अधिक भाग लेते हैं, और निचली जाति के कुछ सदस्य बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं। कई मामलों में, निचली जाति के राजनीतिक नेता निचले पदों पर हैं, और वे अपनी स्थिति से खुश हैं। हाल के दिनों में, त्यागी आंदोलन के प्रभाव ने जाति के राजनीतिक व्यवहार को भी प्रभावित किया है, जिससे जाति की राजनीति के आधार पर रालोद के पक्ष में वोट दिया जाता है और रालोद उम्मीदवार मदन भैया चुनाव जीतते हैं। जातिगत वोटों को एकजुट करने और जाति के बीच एकजुटता बनाने और किसी विशेष पार्टी के पक्ष में या खिलाफ मतदान करने के लिए जाति संगठन प्रमुख साधन हैं। एक महत्वपूर्ण तत्व जाति समीकरण के आधार पर मदन भैया के समर्थन में संयुक्त गुर्जर और जाट वोट थे। मदन भैया की जीत ने हमें यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति दी कि जाति भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि जाति ने लगातार अपने राजनीतिक नेता के समर्थन में खुद को एकजुट दिखाया है।

संदर्भ

1. अप्पादुरई, ए. (2002) डीप डेमोक्रेसीः अर्बन गवर्नमेंटलिटी एंड द होराइजन ऑफ पॉलिटिक्स पब्लिक कल्चर, 14, पृ० सं०–**21–47**।

2. बेंजामिन, डब्ल्यू. (1983) चार्ल्स बौडेलेयरः उच्च पूंजीवाद के युग में एक गीतकार (एच. जोहन, अनुवादक)। लंदनः वर्सो।
3. बौर्डियू, पी. (2000) पास्कलियन ध्यान पालो ऑल्टो, सीएः स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. हॉफमैन, एल. (2006) स्वायत्त विकल्प और देशभक्तिपूर्ण व्यावसायिकताः देर–समाजवादी चीन में शासन व्यवस्था पर अर्थव्यवस्था और समाज, 34, पृ० सं०–**550–70**।
5. जैफ्रेलॉट, सी. (2003) भारत की मौन क्रांतिः उत्तर भारतीय राजनीति में निम्न जातियों का उदय, दिल्ली।
6. जेफरी, आर., जेफरी, पी. और जेफरी, सी. (2005) उत्तर भारत में सामाजिक असमानता और माध्यमिक स्कूली शिक्षा का निजीकरण, आर. चोपड़ा और पी. जेफरी (संपादक), भारत में शैक्षिक व्यवस्था (पृ० सं०–**41–61**), दिल्लीः सेज।
7. जेफरी, सी. (2010ए) टाइमपासः युवा, वर्ग और प्रतीक्षा की राजनीति, पालो ऑल्टो, सीएः स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. जेफरी, सी. (2010बी) टाइमपासः भारत में युवा, वर्ग और समय अमेरिकन एथ्नोलॉजिस्ट, 37(3), पृ० सं०–**465-81**।
9. काट्ज, सी. (2004) वैश्विक स्तर पर आगे बढ़नाः आर्थिक पुनर्गठन और बच्चों का रोजमर्रा का जीवन मिनियापोलिसः यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा प्रेस।
10. कृष्णा, ए. (2002) सक्रिय सामाजिक पूंजीः विकास और लोकतंत्र की जड़ों का पता लगाना, न्यूयॉर्कः कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस।
11. राइट मिल्स, सी. (1959) समाजशास्त्रीय कल्पना, ऑक्सफोर्डः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।